

come forward quickly? And the problem of the Banaras Hindu University is different from the problems of many other Central Universities. Therefore...

MR. CHAIRMAN: You have put the question.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, sometimes, the tendency to come up with piecemeal legislation and piecemeal solution becomes counterproductive. And it has happened in the case of the Central Universities also. Now, we are having a full scrutiny of what is to be done. We have the reports of the Committees, recommendations of the Committees, and decisions of this Parliament as reflected in the New Education Policy and the Programme of Action. Now all this basic material on which wholesome decisions could be taken for legislation are available to us. I don't see why we should not wait for a few months. I am quite sure that it can be done within a few months. So, why should we now be in a hurry to do something piecemeal in the Banaras Hindu University? Maybe the Banaras Hindu University has its own distinctive features and problems. So, has every other University. So, we cannot think of piecemeal legislation for each University. It will confound the matters and lead us nowhere. It is a question of few months. Members could, perhaps, give me any suggestions that they have. We will sit together. We will see how the whole thing has to be put right.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नेचर आफ अमेंडमेंट जो सोचा जा रहा है वह क्या है? और दूसरे माननीय मंत्री जी ने प्रोफेसर्स पर चार्ज की बात कही है। तो एक चार्ज अटल जी ने बताया कि जातिवाद का है, लेकिन उस से भी ज्यादा हीनियस टाइप के चार्ज भी क्या प्रोफेसर्स पर हैं?

श्रीमती कृष्णा साहू : सभापति महोदय, जैसी कि सूचना मिली है उस के अनुसार दो डाक्टरों पर आरोप लगाये गये थे कि एक लेडी पेशेंट के साथ एक ने दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया था और दूसरे डाक्टर पेशेंट से फीस वसूल करने की बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इन्कवाररी के लिये जस्टिस सक्सेना के नेतृत्व में एक कमेटी बनायी गयी जो छानबीन कर रही है और जिस का प्रतिवेदन दिसम्बर में प्राप्त हो जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमान्, इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए। यह प्रश्न बहुत समय से विचाराधीन है :

MR. CHAIRMAN, I have already given half an hour for this. Therefore, we take up next question. Question No. 324.

सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों में मियाद समाप्त हुई दवाओं का वितरण

324. श्री सूरज प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है परिपत्र सं० सी०जी० एच० एस०/एम० एस० डी० आर० एस० 1252, दिनांक 27 जनवरी, 1985 के माध्यम से 13-10-85 को समस्त डिस्पेंसरियों के चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश जारी किये गये थे कि डेक्सा-क्विन की ट्यूबों, जिनकी मियाद नवम्बर, 1986 तक के लिये है, स्टोर में उपलब्ध है, इसलिये उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भंग कर मरीजों में बांट दिया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग 6 महीने पहले ये ट्यूबें सी०जी० एच० एस० स्टोर में उपलब्ध नहीं थीं; और यदि हाँ, तो ये ट्यूबें कहाँ से खरीदी गई थीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सी० जी० एच० एस० के अधिकारियों ने हाल में अक्तूबर, 1986 तक की मियाद वाली (1) बेटनोवेट ट्यूबों, (2) लोकुला

आई ड्राप, (3) वेटनी सोल आई ड्राप की खरीद की थी, जिन्हें डिस्पेंसरियों के डाक्टर मरीजों को अभी भी दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की कोई जांच कराने का विचार रखती है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने सितंबर, 1986 में मेडिकल स्टोर डिपो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को डेक्साक्विन मरहम सप्लाई करने के लिए मांग पत्र भेजा था । मेडिकल स्टोर डिपो के पास तत्काल जो डेक्साक्विन मरहम उपलब्ध था उसकी मियाद नवंबर, 1986 थी । मेडिकल स्टोर डिपो ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को वह माल दे दिया और यह आश्वासन दिया कि इस्तेमाल की मियाद समाप्त होने की तारीख को जो माल बच जाएगा, वह उत्पादक द्वारा बदल दिया जाएगा । औषध की मांग तथा मेडिकल स्टोर डिपो तथा उत्पादक द्वारा दिए गये आश्वासन को देखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने 3,000 ट्यूबों का आर्डर दिया, जो 15 दिन का स्टॉक था और 15-10-1986 से पहले सप्लाई किया जाना था क्योंकि यह आशा थी कि मियाद समाप्त होने की तारीख से पहले ही इसकी खपत हो जाएगी । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को यह मरहम 12-10-1986 को सप्लाई किया गया । 3000 ट्यूबों में से 20 नवंबर, 1986 को केवल 220 ट्यूबें ही शेष बच गई थी, जिन्हें सविदा की शर्तों के अनुसार बदल लिया जाएगा ।

इसी भांति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने लोकला आई-ड्राप्स तथा वेटने-सोल आई ड्राप्स भी निश्चित

नीति के अनुसार मेडिकल स्टोर डिपो से प्राप्त की थी । मियाद समाप्त हुए लोकला तथा वेटनेसोल आई ड्राप्स किसी लाभार्थी को सप्लाई किये गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । रिकार्डों से यह पता नहीं चलता कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने मियाद समाप्त हुई तारीख अर्थात् अक्टूबर, 1986 वाली वेटनीनोवेट मरहम का कोई स्टॉक खरीदा था ।

तीनों औषधों के बारे में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जब वे औषधें मियाद समाप्त होने के बाद लाभार्थियों को जारी की गई हों । अतः पड़ताल कराने के आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सूरज प्रसाद : महोदय, सरकार ने अपने जवाब में यह नहीं स्वीकार किया है कि एक्सपायर्ड दवायें लाभार्थियों में वितरित की गयीं, लेकिन यह आम बात पायी जाती है कि सीजी एचएस के द्वारा एक्सपायर्ड दवायें रोगियों में वितरित की जाती हैं और जो सीजी एचएस के डाक्टर्स होते हैं उन की मिली भगत दूकानदारों से रहती है और डाक्टर्स आम तौर पर जो मुनाफा ऐसी एक्सपायर्ड दवाओं से होता है उसमें भागीदार होते हैं । मैं दूर की बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन माननीय चतुरानन मिश्र जी की बात को ही लीजिए, उन्होंने पटना सीजी एचएस से जो दवायें लीं उसमें डेमेज्ड दवाओं की आपूर्ति की गयी और उन दवाओं का एक पैकेट उन्होंने माननीय मंत्री जी को भी भेजा । सरकार ने जो जवाब दिया है उस के मृतांतिक प्रश्न उठता है और उसके जवाब से यह निकलता है कि सरकार ने डेक्साक्विन मरहम के लिये आदेश दिये सितंबर माह में । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि यह दवा कब खरीदी गई ।

दूसरा प्रश्न मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि आपके जवाब से यह निकलता है कि 20 नवंबर को 220 ट्यूबें बच गईं जो कि एक्सपायर हो गई थीं । क्या वे

220 एक्सपाइड ट्यूब रोगियों को वितरित की गई ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : वस्तुव्य में कहा गया है कि इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा जिसके लिए उनके साथ हमारा करार है। करार के होते हुए क्यों हम बीमारों को वह पुरानी देगे और क्यों उनकी जगह दूसरी नहीं लेगे ?

श्री सूरज प्रसाद : मैंने पूछा था कि कि बच गई थी या नहीं ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : नहीं बच गई थी। जो एक्सपायर नहीं हुई थी वह बच गयी थी। इनको वाटने का प्रश्न ही नहीं उठता जो कि एक्सपायर हो गई थी।

श्री सूरज प्रसाद : श्रीमन्, मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह दवा कहां से खरीदी गई, प्रश्न संख्या 2, में यह पूछा गया था, उसका जवाब नहीं आया। दूसरी बात मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह स्वीकार किया गया है कि एक्सपायर्ड दवाइयां बच गई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन दवाइयों का इन्वेन्टरी-माल हुआ या नहीं, वे एक्सपायर हुई या नहीं, इसके लिए जांच करायी ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : यह कुछ समय में ही नहीं आता है कि आप कुछ आरोप भी लगाते हैं और यह भी कहते हैं कि हम जांच कराएँ। हम कह रहे हैं कि हमारी जांच यह निकली है कि ये नहीं बांटी गई। कहीं यह नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपके पास कोई उदाहरण हो तो मेहरबानी करके हमें दीजिए, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। मेरे पास जो जानकारी है वह मैंने सदन के सामने रख दी है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जवाब देने में चतुर हैं। और किसी भी भाषा में उसका इस तरह से जवाब रख सकते हैं कि सदस्यों को उसमें से कोई सुराग मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह बात निश्चित रूप से सबके सामने है कि बाजारों में एक्सपायर्ड डेट की दवाइयां बिकती हैं

और डाक्टर उसको चलाते हैं। इस बात का मानिटर जो आपके जरिए होना चाहिए या राज्य सरकारों के जरिए होना चाहिए वह नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था आप कर रहे हैं या जो व्यवस्था है उसको टाइटन करने के लिए कदम उठा रहे हैं जो एक्सपायर दवाइयां हैं जो हिन्दुस्तान में 60 से 68 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं, वे नहीं समझ सकते हैं लिखा होने पर भी कि वे एक्सपायर हो चुकी है, उनको होने वाले नुकसान से उनको आप बचा सके ?

श्री पी० बी० नरसिंह राव : इतना आम सवाल होगा तो उतना ही आम जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मानिट्रिंग का हम अर्थ समझें। मानिट्रिंग क्या होता है मानिट्रिंग कभी एक अथॉरिटी के पास से होना आवश्यक नहीं है। कहीं से कोई कम्प्लेंट आ जाए तो वह मानिट्रिंग में आ जाती है हमारे पास जो भी मानिट्रिंग किया जाता है वह हम करते हैं लेकिन हम उसको पर्याप्त नहीं मानते हैं। और क्वांटर्स से आ जाए तो भी हम उसको मानिट्रिंग का भाग बनाएंगे। कोई डाक्टर खुद जाकर कोई दवा नहीं खरीदते हैं। यहाँ मैडिकल स्टोर्स डिपों हैं, वहाँ दवाइयां खरीदी जाती हैं? वहाँ से बांटी जाती है अब हम डाक्टरों को जितनी सख्त हिदायत दें लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि वे खुद खरीदते ही नहीं हैं तो उन पर जिम्मेदारी नहीं आती है। इसके लिए एक संगठन है जो दवाइयां खरीदता है तो आप को जब कभी ऐसी कोई गलती नजर आए तो हमें बता दीजिए, हमसे कहां गलती हुई है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और कार्यवाही भी करेंगे।

श्री नरेश सी० पुगलिया : सभापति महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कबूल किया है कि जिस ट्यूब (आईटमेंट) की एक्सपायरी नवंबर में हुई थी, उसको अक्टूबर में खरीदा गया था और 1 हजार ट्यूब खरीदी गई।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इसकी खरीद के लिए कुछ नाम्स हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाएं मिले इसके लिए सरकार ने कौन से प्रकाशन्स लिये हैं और गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरीज हैं चहिये केन्द्रीय सरकार की हों या राज्य सरकार की हों उसमें जो मेडिसिन के विक्रेता रहते हैं वे जानबूझ कर एक्सपायरी डेट्स की दवाएं भेजते हैं तो इस प्रकार की दवाएं न करने के लिए सरकार ने कोई नाम्स निश्चित किये हैं ?

KUMARI SAROJ KHAPARDB: There are instructions to the medical store organisations (1.) to supply drugs in three instalments in the quarter ending 30th April, 31st August, and 31st December; (2) expiry date of drugs issued should not be less than one year; and (3) items which have been deleted from the formulary, would be accepted upto February; otherwise such orders should be cancelled.

Sir, a separate register is maintained known as Expiry Date Register and the register is updated. We have taken precautions to see that medicines which have crossed expiry date are not issued to the patients.

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : सभापति जी, आदेश और निर्देश सम्बन्धी विभाग से बात निकलती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सुपर बाजार में जो मेडिसिन की दुकान है वहाँ पर एक्सपायरी डेट की दवाएं मिलती हैं जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ पैटीमलशन और एलबोमिन की बोटल जो कि स्वीडन से निर्यात की जाती हैं जिसमें 10-15 दिन के बाद की एक्सपायरी डेट होती है वे दवाएं लोग खरीदते हैं इसके लिए सरकार क्या कर रही है कौन से ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और लास्ट कब गये हैं ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, this is connected with CGHS.

MR. CHAIRMAN: You are repeating the same question. Now, the question No. 325.

Take over of Patna Museum

*325.SHRISHANITYAGI

SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be please to state;

(a) whether it is a fact that Central Government have asked the Director of the National Museum, Delhi to submit a report on the condition of the Patna Museum;

(b) whether the report has since been submitted, if so, what are the contents thereof; and

(c) whether Government propose to take over the Patna Museum?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) No', Sir.

(c) In the event of a proposal to this effect being received from the State Government, it would be considered from all aspects.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, Patna Museum is considered to be one of the finest in our country and some people say that it is one of the finest even in the world. Whatever may be the reasons, whatever may be the actual situation there, as far as the newspaper reports suggest, there are about 43, 000 antiques which are quite valuable and there are many more things representing the Indian

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta.